

प्रेषक,

राम सिंह,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 30 अप्रैल, 2015

विषय— वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड को अनुमन्य फीस दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित दरों पर फीस एवं अन्य सुविधायें दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- |   |   |
|---|---|
| 1- रिटेनर फीस नियत                        | ₹ 40,000/- (₹ चालीस हजार मात्र) प्रति माह     |
| 2- किसी न्यायालय में बहस हेतु अनुमन्य फीस | ₹ 20,000/- (₹ बीस हजार मात्र) प्रति कार्यदिवस |
| 3- आवास पर टेलीफोन सुविधा की सीमा         | ₹ 2,000/- (₹ दो हजार मात्र) प्रति माह         |

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0-04 के अधीन लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-03-महाधिवक्ता-00-16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0- 08 NP /XXVII(5)/2015 दिनांक 22.04.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम सिंह)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 111(1)/XXXVI(1)/2015-105/2012 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- समस्त वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 6- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चौक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

*Arjun*  
30.4.15

(कहकशा खान)

अपर सचिव